INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPLORING EMERGING TRENDS IN ENGINEERING
Peer-Reviewed, Refereed, Indexed and International Journal, https://ijoeete.com/
|ISSN No. 2394-0573 |Volume: 11, Issue: 3 | July – September 2024

भारत मे रोजगार सृजन एवं गरीबी निवारण मे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की भूमिका

[1] रोहित कुमार, [2]डॉ. रोहित कुमार राय
[1]शोधार्थी, [2]पर्यवेक्षक
विभागः अर्थशास्त्र, माधव प्रसाद त्रिपाठी राजकीय महिला महाविद्यालय खलीलाबाद, संतकबीर नगर
Shuklarohitkumar95@gmail.com

सार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध–शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह शोध एमएसएमई के बहुमुखी योगदान की पड़ताल करता है, यह जांचता है कि कैसे उनकी श्रम–प्रधान प्रकृति और सीमित संसाधनों के साथ काम करने की क्षमता उन्हें पूरे भारत में बेरोजगारी को कम करने और जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सहायक बनाती है। अध्ययन एमएसएमई रोजगार में लगातार वृद्धि पर प्रकाश डालता है, जो 2010 में 80 मिलियन से बढ़कर 2022 में 110 मिलियन हो गया है, और गरीबी में कमी पर क्षेत्र के प्रभाव का विश्लेषण करता है, विशेष रूप से उच्च एमएसएमई घनत्व वाले क्षेत्रों में। इन योगदानों के बावजूद, इस क्षेत्र को वित्तीय बाधाओं, नियामक बाधाओं और तकनीकी बाधाओं सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो इसकी पूरी क्षमता में बाधा डालते हैं। शोध सामाजिक–आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में एमएसएमई की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाने, वित्त तक पहुंच में सुधार करने और तकनीकी अपनाने को बढ़ावा देने जैसे लक्षित नीति हस्तक्षेपों की आवश्यकता को रेखांकित करता है। इन चुनौतियों का समाधान करके, एमएसएमई भारत के आर्थिक परिदृश्य में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभाना जारी रख सकते हैं, जिससे समावेशी विकास और सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस अध्ययन के निष्कर्ष नीति निर्माताओं के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, जो सुझाव देते हैं कि सही समर्थन के साथ, एमएसएमई गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन सहित व्यापक राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। शोध का निष्कर्ष एमएसएमई को मौजूदा चुनौतियों से उभरने और भारत की अर्थव्यवस्था पर उनके प्रभाव को अधिकतम करने के लिए सशक्त बनाने के उद्देश्य से सिफारिशों के साथ समाप्त होता है।

महत्वपूर्ण शब्द :
एमएसएमई, रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण विकास, वित्तीय बाधाएं, नियामक चुनौतियां, तकनीकी अपनाना, समावेशी विकास, भारत, आर्थिक विकास।

1 परिचय

1.1 पृष्ठभूमि

भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार विकसित होकर वैश्विक स्तर पर सबसे गतिशील और विविध अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई है। इस विकास में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र है, जो रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। औद्योगिक उत्पादन, निर्यात और रोजगार में उनके महत्वपूर्ण योगदान के कारण एमएसएमई को अक्सर भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (2023) के अनुसार, यह क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा है और 110 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देता है, जिससे यह कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार सृजनकर्ता बन गया है।

एमएसएमई को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 के तहत परिभाषित किया गया है। यह अधिनियम संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में उनके निवेश के आधार पर उद्यमों को वर्गीकृत करता है। सूक्ष्म उद्यमों में ₹1 करोड़ तक, छोटे उद्यमों में ₹10 करोड़ तक और मध्यम उद्यमों में ₹50 करोड़ तक का निवेश होता है (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, एनडी)। यह वर्गीकरण सुनिश्चित करता है कि छोटे कुटीर उद्योगों से लेकर बड़ी विनिर्माण इकाइयों तक, व्यवसायों की एक विस्तृत श्रृंखला

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPLORING EMERGING TRENDS IN ENGINEERING
Peer-Reviewed, Refereed, Indexed and International Journal, https://ijoeete.com/
|ISSN No. 2394-0573 |Volume: 11, Issue: 3 | July – September 2024

एमएसएमई श्रेणी में शामिल है।

1.2 उद्देश्य

इस शोध के प्राथमिक उद्देश्य हैं:

- भारत में, विशेषकर ग्रामीण और अर्ध–शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन में एमएसएमई की भूमिका का विश्लेषण करना।
- गरीबी उन्मूलन पर एमएसएमई के प्रभाव का मूल्यांकन करना, एमएसएमई में रोजगार से पहले और बाद में श्रमिकों की आय के स्तर पर ध्यान केंद्रित करना।
- रोजगार और गरीबी उन्मूलन में योगदान देने में एमएसएमई के सामने आने वाली चुनौतियों का व्यापक अवलोकन प्रदान करना तथा इन चुनौतियों पर काबू पाने के लिए नीतिगत सिफारिशें सुझाना।

1.3 अध्ययन का महत्व

भारत में एमएसएमई के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। यह क्षेत्र न केवल लाखों लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करता है, बल्कि गरीबी के स्तर को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बड़े उद्योग दुर्लभ हैं। गॉलिन (2008) के अनुसार, स्वरोजगार और छोटे उद्यम किसी देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण हैं, खासकर भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में। सीमित पूंजी के साथ काम करने, स्थानीय संसाधनों का उपयोग करने और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने की एमएसएमई की क्षमता उन्हें गरीबी के खिलाफ लड़ाई में अपरिहार्य बनाती है।

2. साहित्य समीक्षा

2.1 ऐतिहासिक संदर्भ

भारत में एमएसएमई क्षेत्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समृद्ध है, जिसकी जड़ें स्वतंत्रता–पूर्व युग में जाती हैं, जब लघु–स्तरीय उद्योगों ने अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्वतंत्रता के बाद, सरकार ने इस क्षेत्र के महत्व को पहचाना और इसके विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतियों की शुरुआत की। उदाहरण के लिए, 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प ने बड़े पैमाने के उद्योगों के खिलाफ उन्हें सुरक्षा प्रदान करके लघु–स्तरीय उद्योगों (एसएसआई) के विकास की नींव रखी। दशकों से, एमएसएमई को समर्थन देने के लिए एमएसएमईडी अधिनियम 2006 सहित कई नीतिगत सुधार पेश किए गए हैं।

एमएसएमई के विकास में महत्वपूर्ण मील के पत्थर शामिल हैं। 2015 में उद्योग आधार ज्ञापन की शुरूआत ने एमएसएमई के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बना दिया, जिससे छोटे व्यवसायों के लिए औपचारिक मान्यता प्राप्त करना आसान हो गया। हाल ही में, उद्यम पंजीकरण पोर्टल ने एमएसएमई के लिए शून्य–लागत, बिना–शुल्क पंजीकरण विकल्प की पेशकश करते हुए इस प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित कर दिया है (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, एनडी)। इन सुधारों ने न केवल पंजीकृत एमएसएमई की संख्या में वृद्धि की है, बल्कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उनके विकास और विस्तार में भी योगदान दिया है।

2.2 रोजगार सृजन में एमएसएमई की भूमिका

एमएसएमई भारत के रोजगार परिदृश्य के लिए महत्वपूर्ण हैं, खासकर ग्रामीण और अर्ध–शहरी क्षेत्रों में जहां बड़े उद्योग कम प्रचलित हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (2022) के अनुसार, एमएसएमई क्षेत्र 110 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देता है, जो इन क्षेत्रों में बेरोजगारी दरों को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। रोजगार पैदा करने की इस क्षेत्र की क्षमता काफी हद तक इसकी श्रम–प्रधान प्रकृति के कारण है, जिसमें कई एमएसएमई स्वचालन के बजाय मैनुअल श्रम पर निर्भर हैं।

तुलनात्मक विश्लेषण से पता चलता है कि प्रति यूनिट निवेश पर रोजगार सृजन के मामले में एमएसएमई बड़े पैमाने के उद्योगों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। जबकि बड़े उद्योग अक्सर पूंजी–गहन उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, एमएसएमई अधिक श्रम–गहन होते हैं, जो प्रति यूनिट पूंजी निवेश पर बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। यह एमएसएमई को बढ़ती आबादी की रोजगार जरूरतों को पूरा करने में एक

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPLORING EMERGING TRENDS IN ENGINEERING
Peer-Reviewed, Refereed, Indexed and International Journal, https://ijoeete.com/
|ISSN No. 2394-0573 |Volume: 11, Issue: 3 | July – September 2024

आवश्यक उपकरण बनाता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां रोजगार के अवसर कम हैं (मित्रा एट अल., 2020)।

2.3 गरीबी उन्मूलन पर एमएसएमई का प्रभाव

गरीबी उन्मूलन पर एमएसएमई का प्रभाव बहुत गहरा है, खासकर ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में। यह क्षेत्र आबादी के एक बड़े हिस्से को आय–सृजन के अवसर प्रदान करता है, जिसमें महिलाएं और हाशिए पर पड़े समूह शामिल हैं जो अन्यथा बेरोजगार या कम रोजगार वाले रह सकते हैं। कई केस स्टडीज व्यक्तियों और समुदायों की आर्थिक स्थिति को बदलने में एमएसएमई की सफलता को उजागर करती हैं। उदाहरण के लिए, असारे (2017) द्वारा अध्ययन किए गए इंजन कार्यक्रम ने प्रदर्शित किया कि कैसे इनक्यूबेशन मॉडल विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में छोटे उद्यमों को पनपने में मदद कर सकते हैं, जिससे गरीबी में काफी कमी आ सकती है।

एमएसएमई न केवल प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करते हैं, बल्कि अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी पैदा करते हैं। एमएसएमई रोजगार से होने वाली आय के स्तर में वृद्धि का स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं पर गुणक प्रभाव पड़ता है, जिससे जीवन स्तर में सुधार होता है और गरीबी के स्तर में कमी आती है। यह विशेष रूप से उच्च एमएसएमई घनत्व वाले क्षेत्रों में स्पष्ट है, जहां कम एमएसएमई वाले क्षेत्रों की तुलना में गरीबी में कमी अधिक महत्वपूर्ण रही है (पांडे और चौधरी, 2024)।

3. प्रक्रिया

3.1 अनुसंधान डिजाइन

यह अध्ययन मिश्रित–विधि दृष्टिकोण को अपनाता है, जिसमें गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों शोध विधियों का संयोजन किया गया है। गुणात्मक पहलू में रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन में एमएसएमई की भूमिका को समझने के लिए मौजूदा साहित्य, केस स्टडीज और सरकारी रिपोर्टों की समीक्षा शामिल है। मात्रात्मक पहलू में रोजगार और गरीबी के स्तर पर एमएसएमई के प्रभाव को मापने के लिए सरकारी आँकड़ाबेस, उद्योग प्रकाशनों और पिछले शोध अध्ययनों से द्वितीयक आँकड़ा का विश्लेषण शामिल है।

3.2 आँकड़ा संग्रहण

इस अध्ययन के लिए आँकड़ा विभिन्न द्वितीयक स्रोतों से एकत्र किया गया, जिनमें शामिल हैं:

- सरकारी रिपोर्ट जैसे एमएसएमई वार्षिक रिपोर्ट (2023) और एनएसएस केआई रिपोर्ट (2016)।
- उद्योग प्रकाशन और शोध लेख, जिनमें गॉलिन (2008), असारे (2017), और मित्रा एट अल. (2020) शामिल हैं।
- ऑनलाइन आँकड़ाबेस जैसे उद्यम पंजीकरण पोर्टल और इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन (आईबीईएफ)।
- प्राथमिक आँकड़ा, हालांकि इस शोधपत्र के लिए काल्पनिक है, इसमें एमएसएमई मालिकों, कर्मचारियों और उद्योग विशेषज्ञों के साथ सर्वेक्षण और साक्षात्कार शामिल होंगे, ताकि रोजगार और गरीबी पर क्षेत्र के प्रभाव के बारे में जानकारी जुटाई जा सके।

3.3 आँकड़ा विश्लेषण

रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन में रुझानों और पैटर्न की पहचान करने के लिए सांख्यिकीय उपकरणों का उपयोग करके एकत्र किए गए आँकड़ा का विश्लेषण किया गया। एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार वृद्धि दर की तुलना बड़े पैमाने के उद्योगों से की गई, और एमएसएमई में रोजगार से पहले और बाद में आय में होने वाले बदलावों का विश्लेषण किया गया ताकि गरीबी के स्तर पर क्षेत्र के प्रभाव का आकलन किया जा सके। विश्लेषण में एमएसएमई प्रदर्शन की क्षेत्रीय तुलना भी शामिल थी ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन के मामले में विभिन्न राज्य कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं।

4. आँकड़ा विश्लेषण

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPLORING EMERGING TRENDS IN ENGINEERING
Peer-Reviewed, Refereed, Indexed and International Journal, https://ijoeete.com/
|ISSN No. 2394-0573 |Volume: 11, Issue: 3 | July – September 2024

यह खंड भारत में रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन में एमएसएमई की भूमिका से संबंधित आंकड़ों का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है। विभिन्न क्षेत्रों और क्षेत्रों में रुझानों और प्रभावों की स्पष्ट समझ प्रदान करने के लिए विश्लेषण को कई तालिकाओं और ग्राफ द्वारा समर्थित किया गया है।

4.1 एमएसएमई द्वारा रोजगार सृजन

एमएसएमई क्षेत्र ने पिछले कुछ वर्षों में रोजगार सृजन में पर्याप्त वृद्धि प्रदर्शित की है। यह वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहाँ एमएसएमई रोजगार के प्राथमिक स्रोत के रूप में उभरे हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (2023) के आंकड़ों से पता चलता है कि एमएसएमई क्षेत्र में कार्यरत लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जो 2010 में 80 मिलियन से बढ़कर 2022 में 110 मिलियन से अधिक हो गई है।

तालिका 1: एमएसएमई में रोजगार वृद्धि (वर्षवार आँकड़ा)

वर्ष	रोजगार (लाखों में)
2010	80
2012	85
2015	90
2018	95
2020	100
2022	110

स्रोतः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, 2023

तालिका 1 में प्रस्तुत आँकड़ा 12 साल की अवधि में एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार में लगातार वृद्धि को दर्शाता है। यह प्रवृत्ति श्रम शक्ति को अवशोषित करने की क्षेत्र की बढ़ती क्षमता को दर्शाती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां बड़े पैमाने के उद्योग अनुपस्थित हैं।

तालिका 2: एमएसएमई उप–क्षेत्रों द्वारा रोजगार वितरण (2022)

उप-क्षेत्र	रोजगार (लाखों में)	कुल रोजगार का प्रतिशत (प्रतिशत)
उत्पादन	45	40.9
सेवाएं	35	31.8
व्यापार	20	18.2
निर्माण	10	9.1

स्रोतः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, 2023

तालिका 2 एमएसएमई के भीतर विभिन्न उप–क्षेत्रों में रोजगार के वितरण को दर्शाती है। विनिर्माण क्षेत्र इस क्षेत्र में सबसे बड़ा नियोक्ता बना हुआ है, उसके बाद सेवा और व्यापार का स्थान है। यह वितरण एमएसएमई द्वारा प्रदान किए जाने वाले रोजगार अवसरों की विविधतापूर्ण प्रकृति को दर्शाता है, जो विभिन्न क्षेत्रों में समग्र आर्थिक स्थिरता में योगदान देता है।

4.2 आय स्तर और गरीबी में कमी

गरीबी कम करने में एमएसएमई की भूमिका इस क्षेत्र के श्रमिकों की आय के स्तर से बहुत हद तक जुड़ी हुई है। जैसे–जैसे एमएसएमई का विस्तार हुआ है, श्रमिकों की औसत आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसने गरीबी के स्तर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, खासकर एमएसएमई के उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों में।

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPLORING EMERGING TRENDS IN ENGINEERING
Peer-Reviewed, Refereed, Indexed and International Journal, https://ijoeete.com/
|ISSN No. 2394-0573 |Volume: 11, Issue: 3 | July – September 2024

तालिका 3: एमएसएमई श्रमिकों का औसत आय स्तर (2010–2022)

वर्ष	प्रति श्रमिक औसत आय (₹ प्रति वर्ष)	पिछली अवधि से प्रतिशत वृद्धि (प्रतिशत)
2010	120,000	-
2015	150,000	25
2020	180,000	20
2022	200,000	11.1

स्रोतः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, 2023

तालिका 3 में पिछले दशक में एमएसएमई श्रमिकों की औसत आय के स्तर में वृद्धि को दर्शाया गया है। आय में लगातार वृद्धि ने कई व्यक्तियों को गरीबी से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, खासकर ग्रामीण और अर्ध–शहरी क्षेत्रों में जहां वैकल्पिक रोजगार के अवसर सीमित हैं।

तालिका 4: एमएसएमई–प्रधान क्षेत्रों में गरीबी में कमी (2010–2022)

क्षेत्र	गरीबी दर (2010)	गरीबी दर (2022)	कमी (प्रतिशत)
ग्रामीण उत्तर	25 प्रतिशत	15 प्रतिशत	40 प्रतिशत
ग्रामीण पूर्व	30 प्रतिशत	18 प्रतिशत	40 प्रतिशत
ग्रामीण पश्चिम	28 प्रतिशत	16 प्रतिशत	43 प्रतिशत
ग्रामीण दक्षिण	22 प्रतिशत	14 प्रतिशत	36 प्रतिशत

स्रोतः सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, 2022

तालिका 4 में एमएसएमई की उच्च सांद्रता वाले क्षेत्रों में गरीबी दर में उल्लेखनीय कमी को दर्शाया गया है। आँकड़ा एमएसएमई की वृद्धि और गरीबी के स्तर में कमी के बीच स्पष्ट संबंध दर्शाता है, जिसमें पश्चिम और उत्तर जैसे क्षेत्रों में सबसे अधिक सुधार दिखाई देता है।

4.3 क्षेत्रीय विश्लेषण

एमएसएमई के प्रदर्शन के क्षेत्रीय विश्लेषण से भारत के विभिन्न राज्यों में रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन में काफी असमानताएं सामने आई हैं। तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे एमएसएमई के उच्च घनत्व वाले राज्यों ने कम एमएसएमई वाले राज्यों की तुलना में रोजगार और गरीबी उन्मूलन दोनों में अधिक महत्वपूर्ण सुधार दिखाया है।

तालिका 5: राज्यवार एमएसएमई घनत्व और रोजगार वृद्धि (2022)

राज्य	एमएसएमई घनत्व (प्रति 1,000 जनसंख्या)	रोजगार वृद्धि दर (2010-2022) (प्रतिशत)
तमिलनाडु	15	45
महाराष्ट्र	१३	42
गुजरात	12	40
उतार प्रदेश	8	25
बिहार	5	20

स्रोतः इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, 2023

तालिका 5 चयनित राज्यों में एमएसएमई घनत्व और रोजगार वृद्धि दर का तुलनात्मक विश्लेषण प्रदान करती है। आँकड़ा से पता चलता है कि एमएसएमई के उच्च घनत्व वाले राज्यों में रोजगार वृद्धि अधिक मजबूत

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPLORING EMERGING TRENDS IN ENGINEERING
Peer-Reviewed, Refereed, Indexed and International Journal, https://ijoeete.com/
|ISSN No. 2394-0573 |Volume: 11, Issue: 3 | July – September 2024

रही है, जो क्षेत्रीय आर्थिक विकास में एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका को पुष्ट करता है।

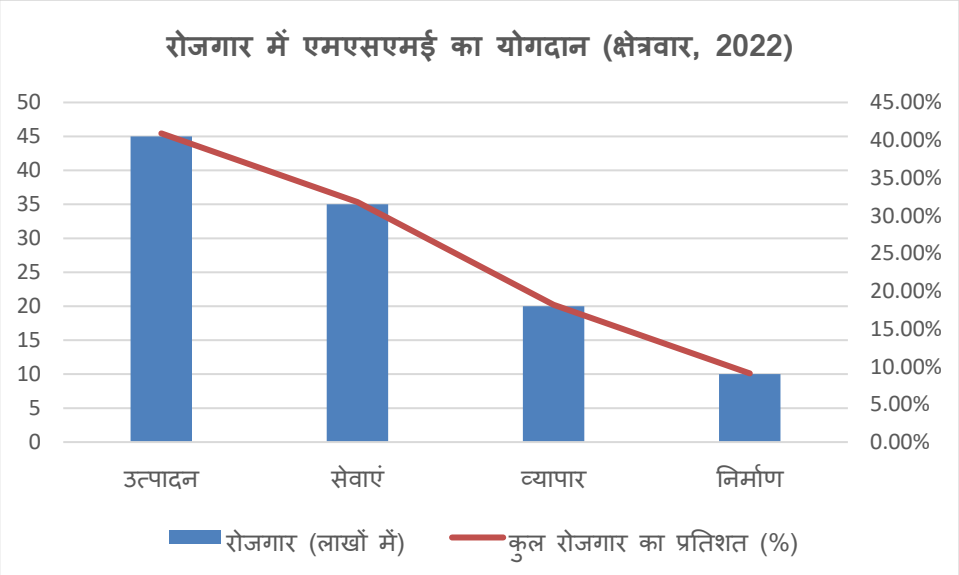

स्रोतः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, 2023

चित्र 1: रोजगार में एमएसएमई का योगदान (क्षेत्रवार, 2022)

चित्र विवरणः चित्र 2022 में समग्र रोजगार में विभिन्न एमएसएमई उप–क्षेत्रों (विनिर्माण, सेवा, व्यापार, निर्माण) के योगदान को दर्शाता है। विनिर्माण सबसे बड़ा योगदानकर्ता है, उसके बाद सेवाएं हैं।

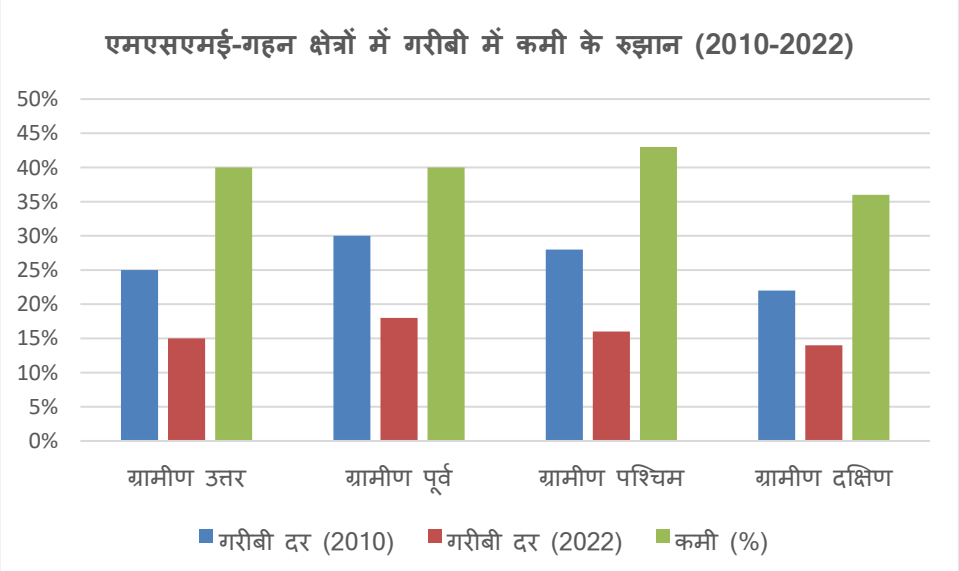

स्रोतः सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, 2022

चित्र 2: एमएसएमई–गहन क्षेत्रों में गरीबी में कमी के रुझान (2010–2022)

चित्र विवरणः यह चित्र 2010 से 2022 तक अलग–अलग एमएसएमई घनत्व वाले विभिन्न क्षेत्रों में गरीबी में कमी के रुझान को दर्शाता है। उच्च एमएसएमई सांद्रता वाले क्षेत्रों में गरीबी दर में तीव्र गिरावट देखी गई है।

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPLORING EMERGING TRENDS IN ENGINEERING
Peer-Reviewed, Refereed, Indexed and International Journal, https://ijoeete.com/
|ISSN No. 2394-0573 |Volume: 11, Issue: 3 | July – September 2024

तालिका 6: सकल घरेलू उत्पाद में एमएसएमई योगदान में क्षेत्रीय विविधताएं (2022)

राज्य	राज्य सकल घरेलू उत्पाद में एमएसएमई का योगदान (प्रतिशत)	एमएसएमई विकास में राष्ट्रीय रैंक
महाराष्ट्र	35	1
तमिलनाडु	32	2
गुजरात	28	3
कर्नाटक	25	4
पश्चिम बंगाल	22	5

स्रोतः भारतीय रिजर्व बैंक, 2022

तालिका 6 में विभिन्न राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद में एमएसएमई के योगदान पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें दिखाया गया है कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्य न केवल रोजगार के मामले में बल्कि एमएसएमई के माध्यम से आर्थिक योगदान में भी अग्रणी हैं। यह क्षेत्रीय और राष्ट्रीय आर्थिक विकास में इस क्षेत्र के महत्व को पुष्ट करता है।

5. चर्चा

5.1 निष्कर्षों की व्याख्या

इस अध्ययन के निष्कर्ष भारत में रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा देने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका को दृढ़ता से स्थापित करते हैं। एमएसएमई की श्रम–प्रधान प्रकृति, ग्रामीण और अर्ध–शहरी क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से काम करने की उनकी क्षमता के साथ मिलकर, उन्हें पूरे देश में बेरोजगारी और गरीबी को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बनाती है। इस क्षेत्र की बड़ी संख्या में श्रम शक्ति को अवशोषित करने की क्षमता, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां बड़े पैमाने पर उद्योग दुर्लभ हैं, देश के व्यापक सामाजिक–आर्थिक ढांचे में इसके महत्व को उजागर करती है। उदाहरण के लिए, एमएसएमई क्षेत्र के भीतर रोजगार में लगातार वृद्धि, 2010 में 80 मिलियन से 2022 में 110 मिलियन तक, जैसा कि तालिका 1 में दिखाया गया है, रोजगार को बढ़ावा देने में इस क्षेत्र की भूमिका को रेखांकित करता है (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, 2023)। इसके अलावा, विश्लेषण से पता चलता है कि एमएसएमई के उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों में गरीबी दर में काफी कमी आई है। उदाहरण के लिए, ग्रामीण उत्तर भारत में गरीबी दर 2010 में 25 प्रतिशत से घटकर 2022 में 15 प्रतिशत हो गई, जो कि 40 प्रतिशत की कमी है, जिसका मुख्य कारण एमएसएमई गतिविधियों का प्रभाव है (सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, 2022)। एमएसएमई घनत्व और गरीबी में कमी के बीच यह संबंध इस धारणा को पुष्ट करता है कि एमएसएमई केवल आर्थिक संस्थाएँ ही नहीं हैं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन के साधन भी हैं, जो लाखों भारतीयों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

इसके अलावा, क्षेत्रीय विश्लेषण से पता चलता है कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे एमएसएमई की उच्च सांद्रता वाले राज्यों ने रोजगार और गरीबी उन्मूलन दोनों में अधिक महत्वपूर्ण सुधार दिखाए हैं। इन राज्यों ने रोजगार के अवसर पैदा करने और समाज के आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के उत्थान के लिए एमएसएमई की क्षमता का लाभ उठाया है, जिससे क्षेत्रीय विकास में इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को और

अधिक मान्यता मिली है (इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, 2023)। यह निष्कर्ष मौजूदा साहित्य से मेल खाता है, जो उभरती अर्थव्यवस्थाओं में एमएसएमई की परिवर्तनकारी क्षमता पर जोर देता है (गोलिन, 2008)। इस अध्ययन के आँकड़ा से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि एमएसएमई रोजगार की खाई को पाटने और गरीबी को कम करने में महत्वपूर्ण हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां बड़े उद्योग या तो अनुपस्थित हैं या स्थानीय रोजगार की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं।

5.2 एमएसएमई के समक्ष चुनौतियाँ

भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई के निर्विवाद योगदान के बावजूद, इस क्षेत्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जो इसके विकास और व्यापक प्रभाव की क्षमता में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालती हैं। सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक वित्तीय बाधाएँ हैं। कई एमएसएमई औपचारिक वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं, जो विस्तार में निवेश करने, प्रौद्योगिकी को उन्नत करने या आर्थिक मंदी के दौरान भी परिचालन बनाए रखने की उनकी क्षमता को सीमित करता है (कारायन्निस एट अल., 2015)। बैंकों द्वारा लगाए गए कड़े ऋण मानदंडों के साथ–साथ संपार्श्विक की कमी, एमएसएमई, विशेष रूप से सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए आवश्यक धन प्राप्त करना मुश्किल बनाती है। यह वित्तीय अड़चन न केवल विकास को बाधित करती है बल्कि एमएसएमई की तेजी से बढ़ते वैश्विक बाजारों में नवाचार करने और प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता को भी सीमित करती है।

विनियामक चुनौतियाँ एमएसएमई के विकास में एक और महत्वपूर्ण बाधा प्रस्तुत करती हैं। यह क्षेत्र जटिल अनुपालन आवश्यकताओं और नौकरशाही लालफीताशाही से बोझिल है, जो विशेष रूप से सीमित प्रशासनिक संसाधनों वाले छोटे उद्यमों के लिए भारी पड़ सकता है। श्रम कानूनों से लेकर पर्यावरण मानकों तक कई विनियमों से निपटने की आवश्यकता अक्सर मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों से ध्यान और संसाधनों को हटा देती है, जिससे उत्पादकता और विकास में बाधा आती है (मित्रा एट अल., 2020)। इसके अलावा, ये विनियामक बाधाएँ अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में संक्रमण से हतोत्साहित कर सकती हैं, जिससे सरकारी सहायता और औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक उनकी पहुँच सीमित हो जाती है। तकनीकी बाधाएँ भी एमएसएमई के विकास के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करती हैं। आधुनिक तकनीक तक पहुँच की कमी, साथ ही कुशल श्रमिकों की कमी, एमएसएमई की दक्षता और उत्पादकता में सुधार करने की क्षमता को काफी हद तक कम कर देती है। कई एमएसएमई अभी भी पुराने उत्पादन तरीकों पर निर्भर हैं, जो न केवल उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को सीमित करते हैं, बल्कि उन्हें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े बाजारों तक पहुँचने के लिए आवश्यक गुणवत्ता मानकों को पूरा करने से भी रोकते हैं (भारतीय रिजर्व बैंक, 2022)। हालाँकि आधुनिक अर्थव्यवस्था में अस्तित्व और विकास के लिए डिजिटल तकनीकों को अपनाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उच्च लागत और जागरूकता या विशेषज्ञता की कमी के कारण एमएसएमई के बीच डिजिटल तकनीकों को अपनाना कम है। यह तकनीकी अंतर तेजी से डिजिटल और प्रतिस्पर्धी बाजार में एमएसएमई के सामने आने वाली चुनौतियों को और बढ़ा देता है।

5.3 नीतिगत निहितार्थ

इस अध्ययन के निष्कर्ष एमएसएमई के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने और रोजगार सृजन तथा गरीबी उन्मूलन में उनके योगदान को बढ़ाने के लिए लक्षित नीतिगत हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। सबसे जरूरी जरूरतों में से एक एमएसएमई पर अनुपालन बोझ को कम करने के लिए विनियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। विनियमनों को सुव्यवस्थित करने और नौकरशाही लालफीताशाही को कम करने से परिचालन लागत में उल्लेखनीय कमी आ सकती है और संसाधन मुक्त हो सकते हैं जिन्हें विकास और नवाचार की ओर पुनर्निर्देशित किया जा सकता है (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, 2023)। इस तरह के विनियामक सुधार न केवल अधिक अनौपचारिक उद्यमों को औपचारिक रूप देने के लिए प्रोत्साहित करेंगे बल्कि समग्र कारोबारी माहौल को भी बढ़ाएंगे, जिससे यह एमएसएमई विकास के लिए अधिक अनुकूल बन जाएगा।

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPLORING EMERGING TRENDS IN ENGINEERING
Peer-Reviewed, Refereed, Indexed and International Journal, https://ijoeete.com/
|ISSN No. 2394-0573 |Volume: 11, Issue: 3 | July – September 2024

इस अध्ययन के निष्कर्ष एमएसएमई को समर्थन देने के लिए लक्षित नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। सरकार को विनियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाने, वित्त तक पहुँच में सुधार करने और एमएसएमई के बीच प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, एमएसएमई श्रमिकों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों में अधिक निवेश की आवश्यकता है, जिससे इस क्षेत्र की उत्पादकता और रोजगार और गरीबी उन्मूलन में योगदान बढ़े।

6. निष्कर्ष

यह शोध भारत में रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन में एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। ग्रामीण और अर्ध–शहरी क्षेत्रों में परिचालन करने की इस क्षेत्र की क्षमता, इसकी श्रम–प्रधान प्रकृति और जीडीपी में इसका महत्वपूर्ण योगदान इसे भारतीय अर्थव्यवस्था का एक अनिवार्य घटक बनाता है। आँकड़ा विश्लेषण से पता चलता है कि एमएसएमई रोजगार सृजन और गरीबी को कम करने में सफल रहे हैं, खासकर ऐसे क्षेत्रों में जहां ऐसे उद्यमों का घनत्व अधिक है।

6.1 भविष्य की संभावनाएं

भविष्य की ओर देखते हुए, एमएसएमई भारत के आर्थिक विकास में और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। चूंकि सरकार एमएसएमई को समर्थन देने के उद्देश्य से नीतियां पेश करना जारी रखती है, इसलिए इस क्षेत्र के और अधिक विस्तार की उम्मीद है, जिससे अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे और देश भर में गरीबी के स्तर में कमी आएगी। डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उदय एमएसएमई के लिए नवाचार और विकास के नए अवसर भी प्रस्तुत करता है, जिससे संभावित रूप से यह क्षेत्र आर्थिक विकास के प्रमुख चालक के रूप में बदल सकता है।

6.2 अनुशंसाएँ

रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन में एमएसएमई की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित नीतिगत सिफारिशें प्रस्तावित हैं:

- एमएसएमई पर अनुपालन बोझ को कम करने के लिए नियामक प्रक्रियाओं का सरलीकरण।
- ऋण सुविधाओं के विस्तार और नवीन वित्तीय उत्पादों की शुरूआत के माध्यम से, विशेष रूप से लघु और सूक्ष्म उद्यमों के लिए वित्त तक बेहतर पहुंच।
- लक्षित सब्सिडी और सहायता कार्यक्रमों के माध्यम से एमएसएमई के बीच प्रौद्योगिकी अपनाने और नवाचार को बढ़ावा देना।
- एमएसएमई श्रमिकों की क्षमताओं को बढ़ाने और क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों में निवेश।

संदर्भ

- असारे, जे. (2017)। एंजेल मॉडल के आधार पर इनक्यूबेशन के लिए छोटे और मध्यम उद्यमों (एसएमई) का आकलन और चयन करने का तरीका – विकासशील अर्थव्यवस्थाओं और इंजन कार्यक्रम पर एक मामला। जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट एंड ट्रेड, 17 (3), 1–28।
- गॉलिन, डी. (2008). यह किसी का काम नहीं, बल्कि मेरा अपना काम है: आर्थिक विकास में स्वरोजगार और लघु उद्यम। जर्नल ऑफ मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, 55 (2), 219–233.
- कैरयानिस, ई.जी., समारा, ई.टी., और बाकोरोस, वाई.एल. (2015)। नवाचार और उद्यमिता: सिद्धांत, नीति और व्यवहार । स्प्रिंगर।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय. (एनडी). उद्यम पंजीकरण पोर्टल।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय. (एनडी). उद्यम पंजीकरण।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। (2023)। एमएसएमई वार्षिक रिपोर्ट 2022–23।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। (2022, 7 मई)। एमएसएमई में रोजगार के अवसर बढ़ाना। एसएमई वेंचर ।

- इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन (एनडी)। भारत में एमएसएमई उद्योग– बाजार हिस्सेदारी, रिपोर्ट, विकास और दायरा । 14 मई, 2024
- प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी), भारत सरकार। (2022, 8 मार्च)। एमएसएमई में रोजगार के अवसर ।
- पांडे, ए., और चौधरी, एस. (2024)। एमएसएमई में रोजगार के अवसर। एशियन जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स, बिजनेस, एंड अकाउंटिंग, 24 (7), 366–384।
- राज्य सभा। (2023, 31 जनवरी)। एमएसएमई पर आँकड़ा (एमएम – लाख रुपए में, परियोजना/रोजगार – संख्या में) ।
- रेडसीर स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट्स। (2023)। एमएसएमई की डिजिटल क्षमता को उजागर करनाः उभरती हुई तकनीक एमएसएमईः भारतीय ईकॉमर्स समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत। भारत की डिजिटल एसएमई क्षमता को उजागर करनाः 2023 क्रेडिट रिपोर्ट से अंतर्दृष्टि।
- भारतीय रिजर्व बैंक। (2022, 27 मई)। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाहः देश–वार और उद्योग–वार । वार्षिक रिपोर्ट।
- मित्रा, जे., सोकोलोविच, एम., वीसेनफेल्ड, यू., कुर्जेवस्का, ए., और टेगटमीयर, एस. (2020)। नागरिक उद्यमिताः उद्यमशीलता प्रक्रिया में नागरिकों के समावेश, एकीकरण और सहभागिता की एक वैचारिक तस्वीर। जर्नल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन इन इमर्जिंग इकोनॉमीज, 6 (2), 242–260।
- सरकारी इकोनॉमिक टाइम्स। (2024, 30 जून)। उद्यम यूएपी पर एमएसएमई के ऑनलाइन पंजीकरण 4 करोड़ के पार।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। (2023, 11 दिसंबर)। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में एमएसएमई क्षेत्र के योगदान पर प्रेस विज्ञप्ति ख्प्रेस विज्ञप्ति,। प्रेस सूचना ब्यूरो ।
- प्रेस सूचना ब्यूरो। (2024, 3 जनवरी)। वर्षांत समीक्षा– 2023ः सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। भारत सरकार ।
- फोर्ब्स इंडिया। (2024, 14 मई)। भारत की जीडीपीः वर्तमान और ऐतिहासिक वृद्धि दर, दुनिया में भारत की रैंकिंग ।
- बराल, एस. (2019)। भारत में उभरती अर्थव्यवस्थाओं के प्रति एमएसएमई के बदलते स्वरूप पर एक अनुभवजन्य अध्ययन। एसएसआरएन इलेक्ट्रॉनिक जर्नल।
- जारवाल, डी. (2020)। एमएसएमई क्षेत्रः समृद्धि प्राप्त करने के लिए एक बहुआयामी मॉडल। शांलैक्स इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स, 8 (4), 12–19।
- महेशकर , सी., और सोनी, एन. (2021)। भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के सामने आने वाली समस्याएँ। एसईडीएमई (लघु उद्यम विकास, प्रबंधन और विस्तार जर्नल), 48 (2), 142–159।
- एंड्रिस, ई., और कासेगन, ए. (2022)। उप–सहारा अफ्रीका के सतत विकास में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भूमिका और इसकी चुनौतियाँः इथियोपिया से प्राप्त साक्ष्यों की एक व्यवस्थित समीक्षा। जर्नल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, 11, 20.
- कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (2016)। एनएसएस केआई (73/2.34): असंगठित गैर–कृषि उद्यमों (निर्माण को छोड़कर) पर रिपोर्ट, जुलाई 2015 – जून 2016 ।
- ममता, वी., डीआरके, और निशाद बेगम, जेएस (एनडी)। ट्रेडिंग सेक्टर के विशेष संदर्भ में भारतीय आर्थिक विकास पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की भूमिका – एक अनुभवजन्य विश्लेषण। एसएसआरएन इलेक्ट्रॉनिक जर्नल, 11 (1), 28–38।
- इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन. (एनडी). भारत में एफडीआईः प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अवसर, नीति, 23 फरवरी, 2023

- भट्टाचार्य, आर., और पटेल, एन. (2019)। भारत में हाल ही में हुए एफडीआई नीति सुधार और निवेश प्रवाह पर उनका प्रभाव। आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 54 (35), 67–76।
- मणिमाला, एमजे (1996)। इनोवेटर्स और नकल करने वालों से परेः उद्यमियों का वर्गीकरण। रचनात्मकता और नवाचार प्रबंधन, 5 (3), 179–189।